आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 29.01.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- आवास सचिव डॉक्टर आर. राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्य समय पर पूरे करने और नई राज्य आवास नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भ्रष्टाचार उन्मूलन में युवाओं की भूमिका को अहम बताया। ईमानदारी और कठोर कार्रवाई पर दिया जोर।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 पेश करेंगी।
- उत्तराखंड को–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन रेशम बुनकरों को चार राज्यों के अध्ययन भ्रमण पर भेजेगी, आधुनिक तकनीक और नए डिज़ाइन से कराया जाएगा परिचय।

समीक्षा बैठक

राज्य में आवास एवं शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रभावी और समयबद्ध प्रगति को लेकर सचिव, आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आवास और शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की राज्य स्तर पर सघन समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट–

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले और दूसरे चरण की प्रगति पर चर्चा करते हुए निर्माण, स्वीकृति और आवंटन से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। सचिव आवास ने कहा कि वर्ष 2017 की उत्तराखंड आवास नीति की वैधता समाप्त हो चुकी है, इसलिए राज्य की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई आवास नीति तैयार की जाएगी। इसमें शहरीकरण की चुनौतियों, किफायती आवास, पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों और सतत विकास को शामिल करने पर जोर दिया गया।

समीक्षा के दौरान देहरादून–मसूरी विकास प्राधिकरण और हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं में लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण के तहत सभी कार्य सितंबर 2026 तक पूरा करने और आवंटन से जुड़ी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट स्टडी के लिए तैयार ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई। सचिव आवास ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों, प्रमुख नगरों और तीर्थस्थलों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए पर्यावरणीय संतुलन के साथ विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

राज्यपाल संबोधन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भ्रष्टाचार समाप्त करने में युवाओं की भूमिका को सबसे अहम बताया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती है और इसे खत्म करने के लिए सामूहिक व निर्णायक प्रयासों की जरूरत है।

राज्यपाल, लोक भवन में राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा आयोजित "यूथ अगेंस्ट करप्शन" विषयक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार देने और लेने वाली सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि ई–गवर्नेंस, तकनीक के बेहतर उपयोग और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाओं से शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है।

राज्यपाल ने भ्रष्टाचार के मामलों में सजा बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि बिना कठोर कार्रवाई के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए युवाओं से ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

जन जन की सरकार

प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे "जन–जन की सरकार जन–जन के द्वार" कार्यक्रम के तहत अब तक 484 विशेष कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे 3 लाख 89 हजार 868 नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। बुधवार को आयोजित 10 कैम्पों में 12 हजार 510 लोगों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ये कैम्प शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं और त्वरित, पारदर्शी तथा प्रभावी सेवा वितरण को सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि इसी प्रतिबद्धता के साथ अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, ताकि राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके।

अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती

जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सफल महिला अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली का आयोजन 18 फरवरी 2026 को ए.एम.सी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम, लखनऊ कैंट में किया जाएगा। यह भर्ती रैली भर्ती निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तथा भर्ती कार्यालय (मुख्यालय), लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित होगी।

इस रैली में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से लगभग एक हजार चयनित महिला अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर जारी किए जा चुके हैं।

अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में अंकित तिथि के अनुसार सुबह चार बजे भर्ती स्थल पर रिपोर्ट करना होगा और अधिसूचना में बताए गए शारीरिक दक्षता परीक्षणों के अनुरूप तैयारी कर सभी आवश्यक दस्तावेज मूल रूप में साथ लाने होंगे। सेना प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बताते हुए अभ्यर्थियों को दलालों से सावधान रहने की सलाह दी है।

आर्थिक सर्वेक्षण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 पेश करेंगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्ग दर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। केंद्रीय बजट 2026–27 पहली फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बजट का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी।

अध्ययन भ्रमण

उत्तराखंड को–ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, प्रदेश के रेशम बुनकरों को चार राज्यों के अध्ययन भ्रमण पर भेजेगी। इसका उद्देश्य बुनकरों को आधुनिक तकनीक, नए डिज़ाइन और उन्नत रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव दिलाना है।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में दून सिल्क के चौथे रिटेल आउटलेट के उद्घाटन अवसर पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अध्ययन भ्रमण से बुनकरों की कार्यकुशलता और दक्षता में वृद्धि होगी और वे अन्य राज्यों की बेहतर तकनीकों को उत्तराखंड में अपनाने में सक्षम होंगे। डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को भ्रमण कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

कार्यक्रम के दौरान बुनाई कार्यशाला आयोजित की गई और सिल्क समग्र परियोजना के तहत लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

फेडरेशन के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ल ने बताया कि फेडरेशन का लक्ष्य 10 हजार महिलाओं को 'लखपति दीदी' के रूप में सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य शहरों में छह और आउटलेट खोले जाएंगे।

स्थलीय निरीक्षण

ऋषिकेश स्थित चन्द्रेश्वर नाले से बिना उपचारित गंदे पानी के गंगा में प्रवाह की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंगा की पवित्रता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और दूषित जल का प्रवाह पूरी तरह रोका जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को नाले के शोधन और सफाई को लेकर विस्तृत रिपोर्ट और कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा में मिलने वाले सभी नालों का जल उपचारित होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चाहे प्रतिष्ठान हों या आवासीय भवन, यदि गंदा पानी गंगा में बहाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नाले में दूषित जल प्रवाहित करते पाए गए 25 घरों के पाइप और ड्रेन्स को सीज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गली–मोहल्लों में जाकर निरीक्षण करते हुए तीन दिन के भीतर नालियों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने के आदेश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता वृद्धि के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने और बिना उपचारित गंदे पानी की रोकथाम को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र में जहां सीवरेज कनेक्शन नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर उपचार की व्यवस्था की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसे बाद में सार्वजनिक किया जाएगा।

आकाशवाणी समाचार, देहरादून

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक– आई आई पी के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में देश के औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7 दशमलव 8 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। ये पिछले दो वर्षों से अधिक समय में सबसे ऊंचा स्तर है। नवंबर में 7 दशमलव 2 प्रतिशत की संशोधित दर के बाद, दिसंबर में भी आईआईपी में बढ़त जारी रही।

एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्ख़ियों पर

उत्तराखंड राज्य में कृषि संबंधी कार्यों और राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर अब सरकार को टैक्स देना होगा। इस ख़बर के साथ नवोदय टाइम्स का शीर्षक है– भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर टैक्स लेगी सरकार.... कृषि कार्यों और पेयजल से इतर उपयोग के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन।

इसी ख़बर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– उत्तराखंड में भूजल के व्यावसायिक प्रयोग पर अब लगेगा शुल्क, कैबिनेट का फैसला। वहीं, अमर उजाला की सुर्ख़ी है– भूजल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर लगेगा शुल्क, ग्रीन हाइड्रोजन नीति मंजूर, आठ प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर, चार ज़िलों में होंगे जनजाति कल्याण अधिकारी।

विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु की ख़बर को सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है.... दैनिक जागरण लिखता है– विमान हादसे में अजित पवार की मौत, मुंबई से बारामती के लिए भरी थी चार्टर्ड प्लेन से उड़ान, चालक दल सदस्यों समेत सभी पांच मारे गए।

राज्य में जल्द गठित होंगी 643 नई पैक्स समितियां। अमर उजाला समाचार बारिश और बर्फबारी से संबंधित ख़बर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित है। अमर उजाला लिखता है– बर्फबारी से आफत, लोग घरों में कैद, आवाजाही का संकट। बर्फबारी से चमोली जिले के 77 से अधिक गांव प्रभावित, हाईवे समेत सात सड़के बंद।